



2026: AHC: 51458-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3966 वर्ष 2026

संतोष (अल्पवयस्क) एवं 4 अन्ययाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिपक्षीगण

याची के अधिवक्ता : विकास यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचियों के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान पीड़ित- संजना को प्रतिपक्षी संख्या 4 के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
2. याचियों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. याचियों द्वारा यह तत्काल रिट याचिका विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.01.2026, जिससे थाना बखिरा, जिला संत कबीर नगर में बी.एन.एस. की धाराओं 85, 115(2), 352, 351(3) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत केस अपराध संख्या 0039 वर्ष 2026 उत्पन्न हुआ है, को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
4. याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याची पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याची संख्या 1- संतोष ने नवनियुक्त प्रतिपक्षी संख्या 4/पीड़िता- संजना, जो प्रतिपक्षी संख्या 3- श्रीमती रमावती देवी की पुत्री है, से कभी विवाह नहीं किया है, हालांकि, केवल झूठे, तुच्छ और अस्तित्वहीन आरोपों पर याचियों के विरुद्ध विवादित प्राथमिकी दर्ज की गई है।
6. याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी दलील दी कि चूंकि याची संख्या 1- संतोष ने संजना-प्रतिपक्षी संख्या 4 से कभी विवाह नहीं किया है, इसलिए वह कभी याचियों के साथ नहीं रही और इसके विपरीत यह आरोप कि उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया था, बिल्कुल पैदा ही नहीं होता और इसलिए, याचियों के विरुद्ध विज्ञापित कोई भी अपराध प्रकट नहीं होता है और विवादित प्राथमिकी अस्तित्वहीन तथ्यों पर आधारित होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि विवादित प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 4/पीड़िता- संजना का विवाह विवादित प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से लगभग तीन महीने पहले याची संख्या 1- संतोष के साथ हुआ था।
8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रतिपक्षी संख्या 4 के साथ याची संख्या 1 के विवाह के संबंध में तथ्य के विवादित प्रश्न की इस रिट याचिका में जांच नहीं की जा सकती है और इस प्रारंभिक चरण में न्यायालय द्वारा अपने रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में तथ्य का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सकता है।
9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे कहा कि विवादित प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लेते हुए, याचियों के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को कि याची संख्या 1 ने प्रतिपक्षी संख्या 4 से कभी विवाह नहीं किया है, सच्चाई का पता लगाने के लिए विवेचना किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए इस चरण में विवादित प्राथमिकी को निरस्त नहीं किया जा सकता है।
10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने और विवादित प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा इस प्रारंभिक चरण में तथ्य के विवादित प्रश्न के संबंध में अपने रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में कोई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथ्यपरक निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सकता है कि क्या याची संख्या 1 का विवाह प्रतिपक्षी संख्या 4 के साथ हुआ था जैसा कि आरोप लगाया गया है, और जिसकी अनुपस्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता कि याचियों के विरुद्ध शिकायत किए गए अपराध नहीं बनते हैं।

11. यहाँ यह बताना भी प्रासंगिक है कि प्रतिपक्षी संख्या 4 के साथ याची संख्या 1 के विवाह का विवादित प्रश्न केवल विवेचना के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर तय किया जा सकता है, जो अभी आना बाकी है और इसलिए, याचियों के विद्वान अधिवक्ता के केवल मौखिक तर्कों पर भरोसा करते हुए, इस प्रारंभिक चरण में याची संख्या 1 और प्रतिपक्षी संख्या 4 के बीच विवाह के तथ्य के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सकता है और उसके आधार पर, इस प्रारंभिक चरण में विवादित प्राथमिकी को निरस्त नहीं किया जा सकता है।
12. पूर्वगामी कारणों से, विवाह के संबंध में तथ्य के विवादित प्रश्न के आधार पर, हमारा यह दृढ़ मत है कि विवादित प्राथमिकी को इस प्रारंभिक चरण में निरस्त नहीं किया जा सकता है।
13. अतः यह तत्काल रिट याचिका गुण-दोष के अभाव में तदनुसार **खारिज** की जाती है।

13 मार्च, 2026

नदीम

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।